खबर संक्षेप

एएसआई रमाशंकर मिश्रा को भावभीनी विदाई

परासिया। थाना रावनवाड़ा परिसर में शनिवार को सेवानिवृत्त हुए सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) रमाशंकर मिश्रा के सम्मान में भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीओपी जितेंद्र जाट, परासिया थाना प्रभारी परासिया ईश्वरी पटले, शिवपुरी रावनवाड़ा थाना प्रभारी कंचन सिंह राजपूत, थाना पुलिस स्टाफ एवं क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एएसआई रमाशंकर मिश्रा ने पुलिस विभाग में लगभग 22 वर्ष की आयु में अपनी सेवा प्रारंभ की थी। करीब 37 वर्ष की लंबी एवं समर्पित सेवा के बाद 31 मई 2026 को शिवपुरी थाना में उनका अंतिम कार्य दिवस रहा। सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित समारोह में उनके उत्कृष्ट कार्यकाल और अनुशासित कार्यशैली को याद किया गया। थाना प्रभारी कंचन सिंह राजपूत ने कहा, कि रमाशंकर मिश्रा समय के बेहद पाबंद अधिकारी रहे हैं। उन्हें यदि सुबह 10 बजे थाना पहुंचना होता था तो वे निर्धारित समय पर ही उपस्थित रहते थे। उन्होंने बताया, कि श्री मिश्रा की क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच अच्छी पकड़ और सकारात्मक छवि रही, जिसकी कमी अब महसूस होगी। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओपी जितेंद्र जाट ने पुलिस सेवा की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कि पुलिसकर्मी अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन परिवार के सहयोग से ही वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं। उन्होंने सेवा काल के अनुभव साझा किया। श्री मिश्रा को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। ग्रामीणों ने पुष्पमालाएं पहनाकर एएसआई मिश्रा का स्वागत किया और उनके साथ स्मृति स्वरूप फोटो खिंचवाकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। वहीं पुलिस स्टाफ ने ढोल - बाजों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया और सम्मानपूर्वक विदाई दी। समारोह भावुक माहौल में संपन्न हुआ।

रेत माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, अधिकारियों से हुज्जत करने वाले भाईयों का निकला जुलूस

कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को पुलिस ने दिया कड़ा संदेश

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

मोहखेड़ विकासखंड में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार से अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 26-27 मई की रात छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मलंग ढाबा के समीप राजस्व विभाग की टीम अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान नायब तहसीलदार रमाकांत चौकसे मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि आशिफ खान और उसका भाई अय्यूब खान वहां पहुंचे और शासकीय कार्रवाई का विरोध करते हुए नायब तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करने तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत दर्ज

कराई गई।

मामले में यह भी आरोप है कि आरोपियों ने नायब तहसीलदार और उनके वाहन चालक का मोबाइल फोन छीन लिया तथा मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई।

लगातार दबिश और तलाश के बाद उमरानाला पुलिस चौकी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई में चौकी प्रभारी राजेश साहू, एएसआई संतोष बघेल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस भी निकाला।

पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश देना था कि शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारियों से अभद्रता करने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर लगाम जरूरी

नायब तहसीलदार से अभद्रता के मामले में पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जिले में अवैध रेत कारोबार से जुड़े तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब सीधे शासकीय अधिकारियों को चुनौती देने लगे हैं। यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रतिष्ठा का भी विषय है। जरूरत इस बात की है कि खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस संयुक्त रणनीति बनाकर अवैध उत्खनन के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करें, तभी रेत और खनन माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। खाकी से सांठगांठ कर हो रहे उत्खनन पर भी जिला प्रशासन नकेल कसने की आवश्यकता है।

पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के माध्यम से यह भी संकेत दिया कि अपराधियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आवश्यक होने पर उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है।

जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में शासकीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई अवैध खनन माफियाओं और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है।

पीएचई उपयंत्री के खिलाफ कलेक्टर को जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 3 ने लिखा शिकायती पत्र

जल जीवन मिशन कार्यों पर सवाल, उपयंत्री पर लापरवाही के आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭ तामिया

जिले की तामिया जनपद पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठकों से लगातार अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनपद अध्यक्ष और सदस्यों का आरोप है कि अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने से क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा और उनका निराकरण प्रभावित हो रहा है।

पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यों ने जनपद पंचायत परिसर में सीईओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ धरना भी दिया था, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसी बीच जनपद क्षेत्र क्रमांक-3 के सदस्य देवी सिंह उइके ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के उपयंत्री राजवीर तोमर के खिलाफ कलेक्टर छिंदवाड़ा को शिकायत सौंपकर जल जीवन मिशन के कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। शिकायत में खापासनी, मानेगांव, बोदल कछार और हरकपुरा पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने के दौरान मानकों के विपरीत खुदाई, फर्जी मूल्यांकन और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के संबंध में पूछे जाने पर उपयंत्री अक्सर बैठक में होने का हवाला देकर फोन काट देते हैं। वहीं तामिया मुख्यालय में एक लाख लीटर क्षमता की प्रस्तावित पेयजल टंकी का निर्माण भी विवादों में घिर गया है। आरोप है कि तकनीकी लापरवाही के चलते टंकी का निर्माण निजी भूमि पर शुरू हो गया, जिसके बाद भूमि स्वामी की शिकायत पर काम बंद करना पड़ा। इसके अलावा पेयजल कूप खनन और री-बोरिंग कार्यों में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक निर्धारित लंबाई की पाइपलाइन नहीं पहुंचाई गई। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जांच होने पर विभागीय कार्यप्रणाली और निर्माण कार्यों में हुई कथित लापरवाहियां उजागर हो सकती हैं।

महिला प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या की, नागपुर में उपचार के दौरान हुई मौत

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

शहर के साहू मोहल्ला क्षेत्र की निवासी महिला प्रधान आरक्षक दीपा नेगी ने कथित रूप से स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उन्हें उपचार के लिए नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपा नेगी पुलिस विभाग में पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवाएं दे रही थीं। उनके पति के निधन के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। विभाग में वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थीं, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने यह कदम उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।

घटना के बाद परिजनों और विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए नागपुर भेजा गया था। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण

उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दीपा नेगी अपने पीछे 15 वर्षीय बेटी को छोड़ गई हैं। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार, परिचितों और पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही सहकर्मियों और स्थानीय लोगों ने भी दुख व्यक्त किया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। परिजनों और संबंधित लोगों के बयान भी लिए जाएंगे, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल सके।

फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणों और परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। मृतका के निधन से पुलिस विभाग ने एक समर्पित कर्मी को खो दिया है, वहीं उनकी बेटी और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, जनसेवा के साथ आंदोलन को मिला जनसमर्थन

छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन दूसरे दिन भी पूरे उत्साह के साथ जारी रहा। प्रदेशव्यापी आंदोलन की कार्ययोजना के तहत 2 जून को आंदोलन के प्रथम दिवस कर्मचारियों ने एनएचएम प्रबंधन द्वारा जारी अप्रेजल संबंधी आदेशों की प्रतीकात्मक प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा शासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। वहीं आंदोलन के दूसरे दिन कर्मचारियों ने जनसेवा का संदेश देते हुए धरना स्थल पर प्याऊ लगाकर आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों का आंदोलन केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और वर्षों से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी है। भीषण गर्मी के बीच धरना स्थल पर कर्मचारियों ने राहगीरों एवं आम नागरिकों को पानी पिलाकर जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली, वेतन विसंगतियों का निराकरण, सेवा सुरक्षा प्रदान करना तथा अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान शामिल है।

डैड लाइन डैड, नहीं खुला अंडर पास अब कांग्रेस देगी धरना

परासिया :- परासिया - तामिया अंडर पास खुलने की डैड लाइन 2 बार डैड हो चुकी है, फिर भी यह मार्ग अबतक नहीं खुला। अब कांग्रेस धरना देने के मूड में है। जिसके लिए कांग्रेस नगर अध्यक्ष वीर बहादुर ने एस डी एम को ज्ञापन भी दे दिया है। परासिया - तामिया मार्ग पर नवंबर 2025 से पुल निर्माण जारी है। निर्माण के लिए 4 अप्रैल तक रेलवे विभाग ने समय निर्धारित किया था और दावा किया था, कि इस अवधि में पुल निर्माण पूरा होकर मार्ग चालू कर दिया जाएगा, लेकिन मार्ग चालू नहीं हुआ। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने 31 मई तक का एक्सटेंशन लिया और मार्ग चालू कर देने का दावा किया। बावजूद इसके मार्ग चालू नहीं हुआ। जिसके चलते अब कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने 3 दिन के अंदर मार्ग चालू नहीं होने की स्तिथि में धरना आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ईधर निर्माण एजेंसी का दावा है, कि 5 जून तक मार्ग चालू कर दिया जाएगा।

कुसमेली मंडी में वर्षों से जमे कर्मचारियों पर उठे सवाल, किसान बोले-आखिर स्थानांतरण सूची कब निकलेगी?

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिन्दवाडा

जिले की कुसमेली कृषि उपज मंडी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला मंडी में वर्षों से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर उठ रहा है। किसानों और व्यापारिक वर्ग के बीच यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि आखिर कुसमेली मंडी में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची कब जारी होगी?

आरोप हैं कि मंडी में कुछ कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से एक ही जगह पर काबिज हैं, जिसके चलते व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। किसानों का कहना है कि शासन की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी संस्थान में लंबे समय तक जमे रहने से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को रोकना होता है। लेकिन कुसमेली मंडी में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। यहां कुछ कर्मचारियों का ऐसा प्रभाव

बताया जा रहा है कि वे वर्षों से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों का कुछ वर्षों में ही तबादला कर दिया जाता है।

स्थानीय किसानों का आरोप है कि मंडी में लंबे समय से जमे कर्मचारियों का अपना मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है। नए अधिकारी या कर्मचारी आते हैं तो उन्हें भी इसी तंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। आरोप यह भी हैं कि मंडी में प्रभावशाली कर्मचारियों का एक ऐसा समूह सक्रिय है जो अपने हितों के अनुरूप माहौल तैयार कर लेता है और वर्षों से अपनी पकड़ बनाए हुए है।

किसानों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी को दो-तीन वर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है तो फिर कुछ लोगों को दो दशक तक एक ही स्थान पर बनाए रखने का औचित्य क्या है?

यह सवाल अब आम किसानों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। उनका मानना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए और यह भी जांच होनी चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान क्या-क्या निर्णय लिए गए तथा उनसे किसे लाभ पहुंचा।

किसानों ने की मुख्यमंत्री यादव से हस्तक्षेप की मांग

किसान संगठनों की मांग है कि वर्षों से जमे कर्मचारियों की सेवा अवधि, कार्यप्रणाली और संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनका दावा है कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। किसानों का कहना है कि मंडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्थानांतरण आवश्यक है। कई किसानों का यह भी कहना है कि कुसमेली मंडी में बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। उनका आरोप है कि कुछ कर्मचारी मंडी की व्यवस्था को अपने प्रभाव क्षेत्र की तरह संचालित करते हैं, जिससे आम किसान और छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि मंडी में वर्षों से जमे कर्मचारियों की सूची तैयार कर तत्काल स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि मंडी प्रशासन में पारदर्शिता आए और निष्पक्ष कार्य संस्कृति स्थापित हो सके। किसानों का सीधा सवाल है जब शासन नियमित स्थानांतरण नीति लागू करता है, तो कुसमेली मंडी में वर्षों से जमे कर्मचारियों पर यह नीति लागू क्यों नहीं हो रही? यही सवाल अब मंडी परिसर से निकलकर जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है।

चपरासी और कोटवार संभाल रहे फाइलें, जनता बेहाल

तहसील भगवान भरोसे: एक बाबू के सहारे चल रही व्यवस्था

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

तहसील कार्यालय मोहखेड़ की प्रशासनिक व्यवस्था इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। कर्मचारियों की भारी कमी के चलते पूरा कार्यालय लगभग एकमात्र बाबू के भरोसे संचालित हो रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई स्थानों पर चपरासी और कोटवार तक बाबुओं का काम करते दिखाई दे रहे हैं।

इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें अपने छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और बार-बार तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण नामांतरण, सीमांकन,

बंटवारा, नक्शा सुधार, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण फाइलों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा। कई मामलों में आवेदनों पर कार्रवाई सप्ताहों तक लंबित रहती है। इससे किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में नियमित बाबुओं की कमी का लाभ कुछ लोग खुलकर उठा रहे हैं। कई बार चपरासी और कोटवार फाइलों की जानकारी देते, आवेदन जांचते और लोगों को निर्देश देते नजर आते हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारियों और अधिकारों की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। इससे न केवल व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि आमजन के मन में भी प्रशासन के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।

बेखौफ चल रहा अवैध वसूली का खेल

क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि ₹काम जल्दी कराने₹ और ₹फाइल आगे बढ़ाने₹ के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। कई ग्रामीणों का कहना है कि दस्तावेज तैयार कराने, आवेदन लगाने या आवश्यक हस्ताक्षर करवाने के नाम पर उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जानकारी लेने आने वाले लोगों के साथ कई बार अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्हें स्पष्ट जानकारी देने के बजाय एक टेबल से दूसरी टेबल तक भटकाया जाता है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोग पूरे दिन कार्यालय में इंतजार करने के बाद भी निराश लौटने को मजबूर हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तहसील कार्यालय में अतिरिक्त बाबुओं की नियुक्ति के लिए कई बार जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं।

ग्राम पंचायत की धीमी कार्यशैली के चलते लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे

15 दिन बाद भी नहीं जुड़ पाई पाइप लाइन, जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिंगोड़ी

ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में पिछले लंबे समय से जल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों को राहत देने के लिए पंचायत ने कुवडी रोड स्थित किसान से भूमि में अस्थाई व्यवस्था बनाने की पहल की थी। करीब 15 दिन पहले पाइप लाइन बिछाई गई लेकिन आज तक पाइप के जॉइंट नहीं जोड़े गए हैं जिस कारण ग्रामीणों को नल से पानी सप्लाई अब तक शुरू हो सका।

ग्रामीणों का कहना है कि पाइप लाइन बिछाने के बाद उम्मीद थी कि जल्द पानी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जॉइंट का काम अधूरा है। इस कारण गांव में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। लोग दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। गर्मी और उमस के बीच पानी की किल्लत से हालात खराब हो रहे हैं। वही ज्यातर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब पाइप लाइन बिछ गई तो जॉइंट का काम क्यों रुका है। 15 दिन में छोटा सा काम पूरा न होना लापरवाही दिखाता है। ग्राम पंचायत की धीमी कार्यशैली के चलते लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं।

पंचायत का टैंकर नदारत,समाज सेवी बांट रहे टैंकर से पानी

पिछले तीन महीनो से सिंगोड़ी की आधी आबादी को नल से पानी नहीं मिला जिस कारण कई शिकायते तथा आंदोलन तक हो गए,अमरवाड़ा विधायक ने एक टैंकर भी पंचायत को दिया है ताकि लोगो को पानी मिल सके परन्तु पंचायत का टैंकर लोगो को पानी पहुंचने में असमर्थ दिखा वही अन्य समाज सेवी जनपत सदस्य योगेश यादव, अमन साहू हर वार्डो के गली मोहल्ले में टैंकर से पानी सप्लाई करते देखे जा रहे है। वही ग्रामीणों ने मांग की है की इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए।

अधिकारियों ने बाल विवाह रुकवाया

जुन्नारदेवः परियोजना जुन्नारदेव अंतर्गत सेक्टर बिलावर कला के ग्राम ढाला पठार पंचायत खमरा कला में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास विभाग की टीम, प्रतिपर्ण संस्था, पुलिस प्रशासन, पंचायत विभाग की संयुक्त टीम विवाह स्थल पर पहुंचकर बालक एवं बालिका के परिवार जनों और रिश्तेदारों को यह विवाह नहीं करने की समझाइस दी गई! बालक की उम्र 19 वर्ष एवं बालिका की उम्र 17 वर्ष पाई गई, यह विवाह 2 वर्ष बाद ही करने की समझाइस दी गई और परिवार जनों ने यह विवाह नहीं करने की सहमति दी है। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग प्रभारी परियोजना अधिकारी सीमा धुर्वे सुनीता चंचल, सेक्टर सुपरवाइजर नीतू वर्मा, सुपरवाइजर रामनाथ उई के, प्रदीपर्ण संस्था,ngoराजकुमार कुमरे,asi, पुलिस विभाग महेश उईके, आरक्षक राजकुमारी बंसल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिव सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

ओवरब्रिज से पहले बनेगा अंडरपास, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

पांढुर्णा। आज 3 जून को नगर में अमरावती रोड पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ब्रिज कार्पोरेशन के अधिकारियों ने स्थल सर्वे किया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि, सर्वप्रथम रेलवे अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद ही रेलवे ओवरब्रिज एवं संबंधित सडक का निर्माण होगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष संदीप घाटोडे भी सर्वे में शामिल हुए। ज्ञात हो कि, यह परियोजना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा नगर के विकास को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नपा अध्यक्ष संदीप घाटोडे के अनुसार नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जिले में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न, 441 किसानों ने किया विक्रय

2669.35 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी, किसानों को 5.81 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सौसर

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में पांढुर्णा जिले में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। किसानों की सुविधा के लिए जिले में 06 पंजीयन केन्द्र बनाये गये थे, जिनके माध्यम से 864 किसानों ने गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराया था।

पंजीकृत किसानों के गेहूं विक्रय के लिए जिले में 03 उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये थे। इनमें 02 केन्द्र पांढुर्णा के शासकीय गोदाम मोरडोंगरी एवं नांदनवाडी में तथा 01 केन्द्र सौंसर कृषि उपज मंडी प्रांगण में संचालित किया गया। तीनों केन्द्रों में कुल 506 किसानों द्वारा स्लॉट बुक कराये गये थे।

शासन द्वारा निर्धारित खरीदी की अंतिम तिथि 28 मई 2026 तक जिले के 441 किसानों ने अपने गेहूं का विक्रय किया। जिले में कुल 2669.35 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। उपार्जित गेहूं के विरुद्ध परिवहन कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

उपार्जन कार्य के साथ-साथ किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से पूर्ण की गई है। अभी तक किसानों को कुल 5 करोड़ 81 लाख 5 हजार 306 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को समय पर उनकी उपज का मूल्य प्राप्त हुआ है।

सीमांकन में देरी, पंच करेंगे धरना प्रदर्शन

शासकीय निर्माण में हो रहा विलंब

हरिभूमि न्यूज ▶▶ परासिया

ग्राम पंचायत भमोड़ी के 17 पंचायत सदस्यों ने शासकीय भूमि के सीमांकन में लगातार हो रही देरी को लेकर तहसीलदार परासिया को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर सीमांकन कार्य नहीं कराया गया तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

पत्र में बताया गया है, कि भमोड़ी बस स्टैंड के समीप स्थित शासकीय भूमि, जो ग्राम भाजीपानी की सीमा से लगी हुई हैb, के खसरा नंबर 116, 117 एवं 118 का सीमांकन कराने के लिए पंचायत द्वारा वर्ष 2023 से प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा 6 फरवरी 2023 तथा 25 जून 2025 को सीमांकन किया गया, लेकिन दोनों सीमांकन में भारी अंतर पाए जाने से विवाद की स्थिति बनी हुई है।पंचायत का

आरोप है, कि सीमांकन संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मामले की जानकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को भी दी गई थी, जिसके बाद पुनः सीमांकन के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है।

पंचायत द्वारा 6 मई 2026 को भी तहसीलदार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है इस बार भी सीमांकन के लिए पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है, कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे सीमांकन कार्य और अधिक कठिन हो जाएगा।

सीमांकन नहीं होने के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही बस स्टैंड के समीप स्थित शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की आशंका भी बढ़ रही है। जबकि इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा कई निजी भूमि के सीमांकन किए गए हैं।

ग्राम पंचायत भमोडी के सरपंच विपिन श्रीवास्तव ने बताया, कि उपरोक्त चिन्हित खाली जमीन बस स्टैंड के पास होने के कारण कई बार अवैध अतिक्रमण की कोशिशें हुई हैं। वहां पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है, लेकिन सीमांकन नहीं होने से आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है जिसको लेकर पंचगणों और ग्रामवासियों में असंतोष है।

माय भारत केंद्र ने विश्व साइकिल दिवस पर निकाली साइकिल रैली

छिंदवाड़ा। माय भारत केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा विश्व साइकिल दिवस का आयोजन जिला युवा अधिकारी सुष्मा गवली के मार्गदर्शन में अर्पण शिक्षा एवं जन कल्याण समिति के द्वारा स्थानीय खापाभाट वार्ड क्रमांक 10 मे मुख्य अतिथि पार्षद संगीता उईके, नगर मंडल 1 के महामंत्री कमलेश कवरेती वरिष्ठ समाजसेवी श्यामल राव,अर्पण शिक्षा समिति के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, मातृ सेवा संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रमुख वक्ता डा महेश बंदेवार की उपस्थिति मे विश्व साईकिल दिवस मनाया गया ।इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने बताया कि माय भारत केंद्र के तत्वावधान में विभिन्न गतिविधियों में निबंध लेखन, ,पौधरोपण,गोष्ठी साइकिल रैली ,पैदल रैली का आयोजन किया गया । इस अवसर पर आयोजन प्रभारी श्यामल राव ने बताया की प्रातः 8 बजे वार्ड क्रमांक 10 खापाभाट माध्यमिक शाला परिसर से सायकिल रैली को हरी झंडी वार्ड पार्षद श्रीमती संगीता ऊईके के द्वारा दिखाकर शुभारंभ किया गया।

वारासिवनी में संत समागम के रूप में एक विशाल आध्यात्मिक सत्संग संपन्न

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रमित जी के पावन आशीर्वाद से वारासिवनी में संत समागम के रूप में एक विशाल आध्यात्मिक सत्संग संपन्न हुआ। जहां मिशन के परम् अनुयाई हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से पहुंचे संत परम् आदरणीय महात्मा तिलकराज जी डोगरा के पावन हुजूरी में सद्गुरु के संदेश को सैकड़ो श्रद्धालुओं के बीच सांझा किया गया।

मानव जीवन का असल मकसद भक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है, इसके लिए पूर्ण सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं और भगत को मोक्ष के काबिल बनाते हैं। संत निरंकारी मिशन के अनुयाई सद्गुरु के संदेश को जन-जन तक पहुंचाते हैं ऐसे आध्यात्मिक सत्संग मिशन के द्वारा देश और विदेश में हो रहे हैं। जहां मिशन के प्रमुख सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश विदेश में प्रचार यात्राओं के द्वारा मानव को मानवता के गुणो से सजा रहे हैं और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान देकर मानव जन्म को सार्थक कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन मानव के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत कर रहा है, ताकि हर कोई प्यार, नम्रता, भाईचारा वाला जीवन जीकर सारे संसार में सुकून का वातावरण बना सके।

पंचायत के दरवाजे पर वर्षों से दबंगई का डेरा, पराली के ढेर ने निगल ली स्वच्छता, जिम्मेदार बने मूकदर्शक

परसवाड़ा पंचायत परिसर में फैली गंदगी पर प्रशासन की चुप्पी, शिकायत करने वालों को राजनीतिक रसूख का डर दिखाने का आरोप

हरिभूमि न्यूज लांजी। सरकार एक ओर स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च कर गांव-गांव साफ-सफाई का संदेश दे रही है, वहीं जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाड़ा में इस अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंचायत भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर वर्षों से पराली और कृषि अवशेषों का ढेर जमा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे हटाने की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पंचायत परिसर, जो ग्रामीण प्रशासन और जनसेवा का केंद्र माना जाता है, वह आज गंदगी और अव्यवस्था का प्रतीक बनकर रह गया है। ग्रामीणों के अनुसार प्रताप कोरकु द्वारा पंचायत परिसर के गेट पर लगातार पराली जमा की जाती है। देखते ही देखते यह स्थान निजी भंडारण स्थल में तब्दील हो गया, लेकिन पंचायत प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। स्थिति यह है कि पंचायत भवन में आने वाले ग्रामीणों को गंदगी और अव्यवस्था के बीच से होकर गुजरना पड़ता है।

शिकायत करो तो मिलता है रसूख का जवाबः ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी इस मामले को लेकर आपत्ति जताई जाती है तो संबंधित व्यक्ति कथित तौर पर राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का हवाला देकर लोगों को चुप कराने की कोशिश करता है। ग्रामीण बताते हैं कि खुलेआम यह कहा जाता है कि जनपद सदस्य मेरा है, विधायक मेरा है, जो करना है कर लो। इस तरह की कथित दबंगई के कारण कई लोग खुलकर विरोध करने से भी बचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत परिसर जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का कब्जा वर्षों तक बना रह सकता है, तो यह स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सरपंच और सचिव की निष्क्रियता से बढ़ा आक्रोशः मामले में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने वर्षों से चली आ रही इस समस्या को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की। वहीं सचिव पर भी उच्च अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराने के आरोप लग रहे हैं।परिणामस्वरूप पंचायत परिसर की बदहाल स्थिति लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक ओर गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर पंचायत के मुख्य द्वार पर वर्षों से जमा पराली का ढेर स्वच्छता अभियान को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। लोगों ने जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से तत्काल जांच कर परिसर को अतिक्रमण एवं गंदगी से मुक्त कराने, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने तथा पंचायत परिसर की गरिमा बहाल करने की मांग की है।

उच्च श्रेणी शिक्षक अरमरकर को सेवा निवृत्ति पर ससम्मान दी गई विदाई

हरिभूमि न्यूज किरनापुर। शासकीय माध्यमिक विद्यालय नक्शी के उच्च श्रेणी शिक्षक सम्माननीय विजय कुमार अरमरकर को सेवा निवृत्ति पर ससम्मान विदाई दी गई। समारोह में संकुल प्राचार्य श्री इन्द्रश्याम ठाकरे ने सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देकर और श्रीफल व शाल भेंटकर सम्मान किया। आपको बता दे की विजय कुमार अरमरकर का जन्म 16/05/ 1964 में नक्शी में हुआ, इनके पिता स्वर्गीय श्री चुणामन अरमरकर माता स्वर्गीय श्रीमती शारुबाई अरमरकर उनकी प्रथम नियुक्ति 6/8/ 1982 को बालाघाट बीटीआई प्रशिक्षण में, शासकीय प्राथमिक शाला नक्शी मे 1984 से 1989 तक, शासकीय प्राथमिक शाला वारा में 1990 से 91 तक, शासकीय हाई स्कूल राजेगाव 1991 से 1994 तक, शासकीय माध्यमिक शाला लांजी में 1994 से 2002 व शासकीय माध्यमिक शाला रिसेवाड़ा में 2003 से 2004 तक, शासकीय प्राथमिक शाला मुंडेसरा 2009 से 2014 तक, अंत में शासकीय माध्यमिक शाला नक्शी में 2014से 31 /4/.2026 तक संपूर्ण सेवा में कुल 43 साल 9 माह अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग को दी। प्राचार्य ठाकरे ने शिक्षक विजय कुमार अरमरकर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए समर्पित कार्यों की सराहना की। शिक्षक केदार सिंह बिसेन, अशोक कुमार उइके, दीप्ति, मनोहर बिसेन, चुन्नी लाल ढोमने, रवि कटंगकर, कृष्ण कुमार पारधी,संगीता नायक,आदि ने शिक्षक विजय कुमार अरमरकर के स्वस्थ, सुखद व मंगलमय जीवन की कामना की।

पूर्व पार्षद ने नगर पालिका परिषद पर लगाए भेदभाव के आरोप

परिषद में बैठे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि करते है भेदभाव-सुनील पिपरेवार

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। हम बड़े लोग तो अपने मनोरंजन के साधन ढूंढ लेते है। कुछ मोबाइल पर, कुछ टीवी पर तो कुछ दोस्तो के साथ अपना समय बीता कर अपना मन बहला लेते है। बच्चों के लिए खिलौने होते है, पार्क होते है।इनसे ही बच्चे अपना मन बहलाते है। पार्क में कई झूले होते है। जो बच्चों के लिए लगाए जाते है। इन पर बच्चे खेलकर काफी खुश होते है।अगर बगीचे में लगे झूले ही जर्जर हालात और नाजुक स्थिति पर हो तो कब हादसा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

कुछ ऐसा ही वारासिवनी गांधी बाल उद्यान का हाल है।जहां बच्चों के लिए लगे झूले की स्थिति दयनीय है और परिषद में बैठे जिम्मेदार लोग खामोश बैठे हुए है। लेकिन इस खामोशी को तोड़ते हुए वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सुनील पिपरेवार ने परिषद में बैठी अपनी ही भाजपा की परिषद पर शहर की अनदेखी का आरोप लगाकर भाजपा की नगर सरकार को ही घेर लिया हैं।

वॉर्ड नम्बर 5 के पूर्व पार्षद सुनील पिपरेवार ने चर्चा में बताया कि नगर के वार्ड नंबर 5 में स्थित गांधी बाल उद्यान बालाघाट जिले का सर्वश्रेष्ठ बगीचा कहलाता है। इस बगीचे में रोजाना सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में शुद्ध हवा के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता को देखने नागरिकों व बच्चों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बगीचे में मेंटनेंस और देखरेख के मामले में नपा फिसड्डी हैं। उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से स्टील की रेलिंग लगाई गई थी, जो वर्तमान में पूरी तरह टूट गई हैं। लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नही गया हैं।यही नही इस उद्यान में महिला और पुरुष के व्यायाम के लिए लाखों रुपये खर्च कर एक्सरसाइज उपकरण लगाए गए थे, जो देखरेख के अभाव में खस्ताहाल हो गए है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस उद्यान में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था ना होने की वजह से उन्हें असामाजिक शोहदों के अमर्यादित हरकतों का शिकार होना पड़ता हैं। जिस ओर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नही हैं। उन्होंने बताया कि कई बार इन असामाजिक शोहदों की वजह से परिवारों के साथ घूमने आई महिला सदस्यों को बेहद शर्मसार होना पड़ता हैं।

भाजपा नेता श्री पिपरेवार ने बताया कि नपा ने यहाँ दो कर्मचारियों को बगीचे की देखरेख व व्यवस्था बनाने के लिए रखा हैं। लेकिन दोनों ही कर्मचारी दिव्यांग हैं। जबकि बगीचे जैसे स्थल पर देखरेख के लिए हर तरह से सामान्य कर्मचारी को रखना चाहिए। लेकिन लगता हैं कि नपा के पास करीब दो सौ कर्मचारियों में से एक भी कोई ऐसा सामान्य कर्मचारी नही हैं, जिसकी तैनाती बगीचे में की जा सके, इसलिए इन दो दिव्यांग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं।

सरपंच की शिकायत पर प्रशासन ने लिया एक्शन

सड़क काटकर किया जा रहा था अवैध अतिक्रमण

हरिभूमि न्यूज कटंगी। कटंगी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेकाड़ी (म.) में सड़क काटकर कृषि भूमि तैयार करने और अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। इस घटना ने ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासनिक हलकों में चिंता पैदा कर दी है। सरपंच ओमप्रकाश उइके ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई और सीमांकन की मांग की। दरअसल, ग्राम टेकाड़ी से होकर भसियागढ़ महादेव खोली की ओर जाने वाली कच्ची सड़क को कुछ किसानों ने अवैध रूप से काटकर अपनी कृषि भूमि में शामिल कर लिया। यह रास्ता न केवल धार्मिक स्थल तक जाता है बल्कि गांव के तमाम किसान इसी मार्ग से अपने खेतों तक पहुंचते हैं। सड़क काटे जाने से ग्रामीणों को भविष्य में मिट्टी के अधिक कटाव की वजह से आवाजाही बाधित होने की संभावना थी और इसी को लेकर गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही सरपंच ओमप्रकाश उइके को इस अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर अतिक्रमण से ग्रामीणों को भारी असुविधा हो रही है और यह सार्वजनिक मार्ग है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा असंवैधानिक है।

तहसीलदार राकेश प्रजापति ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व निरीक्षक और पटवारी की टीम मौके पर भेजी। टीम ने सीमांकन कर जांच की और पाया कि सड़क को अवैध रूप से काटा गया है। सीमांकन रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि किसानों ने सड़क की भूमि को अपने खेतों में मिलाकर अतिक्रमण किया है। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह मार्ग वर्षों से गांव की सार्वजनिक सुविधा का हिस्सा रहा है। अतिक्रमण से न केवल धार्मिक स्थल तक पहुंचना कठिन हो गया है बल्कि किसानों की दैनिक आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और सड़क को यथावत किया जाए। सरपंच ओमप्रकाश उइके ने कहा कि गांव की सड़क पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर सड़क को यथावत किया जाए।

जिले के सभी विद्यालयों में 1 से 30 जून तक मनाया जाएगा मेगा APAAR दिवस

बालाघाट। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 1 जून से 30 जून 2026 तक ₹मेगा APAAR दिवस₹ का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष अभियान प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों की APAAR आईडी बनाना और उन्हें डिजिटल शैक्षणिक पहचान से जोड़ना है। जिला परियोजना समन्वयक श्री जीपी बर्मन ने बताया कि इस कार्यक्रम में ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाएगा, जिनकी APAAR आईडी अभी तक नहीं बनी है। अभियान के तहत विशेष रूप से दो श्रेणियों के विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, पहले वे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है लेकिन APAAR आईडी नहीं बनी है, तथा दूसरे वे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं है।

भारी डीजल संकट से जूझ रहा अन्नदाता

खेतों में थम रहे ट्रैक्टर के पहिए, चिंतित किसान

खेत बुवाई पर मंडराया संकट बिना डीजल कैसे होगी खेती? चीखता किसान

राकेश अगरवार/ हरीभूमि बरघाट। अभी वर्तमान समय में जिसकी कोई सुनने वाला कहीं नहीं है जिसकी माली हालत हर तरफ से। बद से बत्तर होती जा रही है वही सबका पेट भरने वाला मेहनत कस मजबूर इंसान किसान लोग हैं जो हर तरह से लाचार होते नजर आ रहे हैं जिनकी वर्तमान में ना तो शासन प्रशासन सुनाई कर रहा है और ना ही केंद्र और राज्य सरकारें जिले में डीजल आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट अब किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। खरीफ सीजन की तैयारी के बीच खेतों में जुताई और बुवाई का कार्य प्रभावित होने लगा है।

किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक निर्देशों के चलते पेट्रोल पंपों पर डिब्बों में डीजल देना बंद कर दिया गया है, जिससे खेती-किसानी के कार्यों में गंभीर अवरोध पैदा हो रहा है। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर खेतों में काम करते समय अचानक डीजल खत्म हो जाने पर बीच खेत में खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर को धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक ले जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद किसानों को डिब्बों में डीजल देने से इंकार किया जा रहा है, जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं।

वर्तमान बुवाई के समय बढ़ी किसानों की चिंता

मानसून की दस्तक के साथ किसान खेतों की तैयारी में जुटे हैं। जुताई, बखरनी और बुवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन दिनों तेजी से किए जाते हैं, लेकिन डीजल की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई गांवों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि पर्याप्त डीजल नहीं मिलने के कारण ट्रैक्टर मालिक खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय पर जुताई और बुवाई नहीं हुई तो फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, ट्रैक्टर मालिकों ने बढ़ाए किराए डीजल संकट का असर ट्रैक्टर किराए पर लेने वाले किसानों पर भी दिखाई देने लगा है। डीजल की सीमित उपलब्धता और बढ़ती लागत के कारण कई ट्रैक्टर मालिकों ने जुताई के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि पहले जहां निर्धारित दरों पर खेतों की जुताई हो जाती थी, वहीं अब डीजल संकट के कारण किराए में मनमानी बढ़ोतरी की जा रही है।

डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए ट्रैक्टर मालिको ने भी बड़ाए खेत जुताई के हिसाब में अत्यधिक दाम किसानों का फूटा गुस्सा

क्षेत्रीय ब्लॉक और जिला स्तर के पेट्रोल पंप संचालक भी परेशान

सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप संचालक भी इस स्थिति से परेशान हैं। उनका कहना है कि डीजल की आपूर्ति सीमित मात्रा में हो रही है, जिसके कारण ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है।कई पंप संचालकों के अनुसार उन्हें निर्धारित मात्रा में ही डीजल मिल रहा है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है।

प्रभारी जिला कलेक्टर से की विशेष अनुमति की मांग

किसान संगठनों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि किसान की पहचान और भूमि संबंधी दस्तावेज देखकर उन्हें डिब्बों में डीजल देने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका कहना है कि इससे खेती-किसानी के कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे और किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

डीजल संकट पर किसानों की चेतावनी:नहीं मिला समाधान तो होगा घेराव

किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही डिब्बों में डीजल देने की व्यवस्था बहाल नहीं की गई और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त डीजल उपलब्ध नहीं कराया गया, तो जिले भर के किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि अन्नदाता की समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यदि समय पर कृषि कार्य प्रभावित हुए तो इसका असर पूरे क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा। अब सबकी नजर प्रशासन पर खरीफ सीजन की शुरुआत के बीच डीजल संकट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़े ट्रैक्टर, अधूरी जुताई और बुवाई की तैयारी में लगे किसान अब जिला प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांगों पर कितना गंभीरता से विचार करता है और इस संकट का समाधान कितनी जल्दी निकालता है। आखिर इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है क्या जिला प्रशासन किसानों को इस भयावाह बिकट संकट से निकाल पाएगा या नहीं यह समझ के परे है।

छोटे बड़े किसानों का 5 से 10 लीटर डीजल की सीमा से नहीं चल पा रही खेती

ग्रामीण इलाकों के किसानों ने पत्रकार राकेश अगरवार को बताया की कई पेट्रोल पंपों पर एक बार में मात्र लगभग 5 से 10 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है। इतनी मात्रा में डीजल दो एकड़ भूमि की जुताई में ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद किसान फिर डीजल के लिए भटकने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि खेती में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि यंत्रों के लिए पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

कोतवाली पुलिस की तत्परता से 8 घंटे में मिला खोया बैग, 8 तोला सोना सुरक्षित लौटाया

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोया हुआ बैग महज 8 घंटे के भीतर बरामद कर उसमें रखे लगभग 8 तोला सोने के आभूषण सुरक्षित रूप से उनके स्वामी को लौटाकर ईमानदारी और कार्यकुशलता का परिचय दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राय की बहन एवं अधिवक्ता प्रीति राय 1 जून 2026 को स्कूटी से बाजार आई थीं। इसी दौरान नगर पालिका चौक के पास उनका बैग कहीं गिर गया। बैग में लगभग 8 तोला सोने के आभूषण रखे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही मामले को कृष्ण लालचंदानी के संज्ञान में लाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर बैग का पता लगा लिया और उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। बरामद बैग में रखे सभी सोने के आभूषण सुरक्षित पाए गए, जिन्हें विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर सुश्री प्रीति राय को सौंप दिया गया।

पुलिस की तत्परता, ईमानदारी एवं उत्कृष्ट कार्यशैली से प्रभावित होकर प्रदीप राय एवं उनके परिवार ने इस सराहनीय कार्य में शामिल पुलिस टीम के सम्मान स्वरूप 21,000 का चेक पुलिस अधीक्षक को भेंट किया। सिवनी पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा, सहायता एवं विश्वास बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस आमजन की सेवा के लिए सदैव तत्पर है।

मांगों के निराकरण नहीं होने से बड़ा असंतोष, एमडीएम को सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कुरई। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की तहसील शाखा कुरई ने अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर 8 जून से 10 जून 2026 तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संघ द्वारा तहसीलदार कुरई को आवेदन सौंपकर अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार धुर्वे के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन में बताया गया है कि मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा 2 जून 2026 को प्रदेश सरकार के समक्ष विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। मांगों के निराकरण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश संगठन के आह्वान पर यह कदम उठाया जा रहा है। संघ के अनुसार तहसील कुरई के सभी पटवारी 8, 9 एवं 10 जून को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके लिए संबंधित पटवारियों की सूची भी प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है तथा नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। पटवारी संघ का कहना है कि वे लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। कई बार ज्ञापन और निवेदन देने के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं होने से उन्हें सामूहिक अवकाश का सहारा लेना पड़ रहा है। पटवारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से तहसील क्षेत्र में नामांतरण, बंटवारा, आय-जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े सत्यापन कार्य, फसल गिरदावरी सहित विभिन्न राजस्व कार्य प्रभावित होने की संभावना है। आम नागरिकों को भी इन दिनों राजस्व संबंधी सेवाओं में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पटवारी संघ ने उम्मीद जताई है कि शासन एवं प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर न जाना पड़े।

विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, आर्थिक सहायता स्वीकृत

सिवनी। सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने बुधवार को ग्राम ढुकली पहुंचकर हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे में प्रभावित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया तथा त्वरित आर्थिक सहायता स्वीकृत की।

गौरतलब है कि बीते दिनों ग्राम ढुकली में एक निर्माणाधीन कुएं के कंक्रीटीकरण कार्य के दौरान तराई करते समय अचानक मिट्टी धंस जाने से बड़ा हादसा हो गया था। इस दुर्घटना में 42 वर्षीय अनुसूईया जंघेला एवं उनकी 17 वर्षीय पुत्री स्वाति जंघेला की मलबे में दबने से असामयिक मृत्यु हो गई थी, जबकि परिवार की बुजुर्ग सदस्य समनिया बाई जंघेला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।

उन्होंने परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए इस कठिन समय में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद विधायक जिला चिकित्सालय सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लगभग 75 वर्षीय समनिया बाई जंघेला का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा कर बेहतर उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात विधायक दिनेश राय मुनमुन ग्राम चंदौरी पहुंचे और वहां दिवंगत जुगल किशोर के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

तथ्यों को छिपाने के गंभीर आरोप में प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत सेवा से पृथक

प्रधान आरक्षक 490 योगेश राजपूत जिला सिवनी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ कि प्रधान आरक्षक 490 योगेश राजपूत ने पुलिस विभाग में भर्ती के समय अनुप्रमाणन फार्म में आपराधिक प्रकरण की जानकारी जानबूझकर छिपाई।

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

प्रधान आरक्षक 490 योगेश राजपूत के विरुद्ध थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा में अपराध क्रमांक 233/97 धारा 279,337 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत भी वर्ष 1997 में आरक्षक भर्ती के समय अनुप्रमाणन फॉर्म में अपराध की जानकारी को छिपाया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अपचारी के विरुद्ध विभाग में आने के बाद जिला सिवनी में 02 एवं जिला बालाघाट में 01 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, जो वर्तमान में विवेचनाधीन/माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए भर्ती प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाना गंभीर कदाचार एवं संदिग्ध आचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक, छिंदवाड़ा रेंज द्वारा प्रधान आरक्षक 490 योगेश राजपूत को सेवा से पृथक किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

रजवाड़ा के विवेक अग्रवाल नागपुर में हुए सम्मानित

इवेंट मैनेजर डे समारोह में मिला टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सम्मान

हरिभूमि न्यूज सिवनी। सिवनी के युवा इवेंट मैनेजर एवं गुरु कृपा इवेंट्स के संचालक विवेक अग्रवाल को नागपुर में आयोजित इवेंट मैनेजर डे सेलिब्रेशन एंड इंडस्ट्री मीट के दौरान सम्मानित किया गया। उन्हें इवेंट इंडस्ट्री में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया गया। नागपुर इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मई को इवेंट मैनेजर डे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी नागपुर के सेंटर प्वाइंट होटल में आयोजित समारोह में इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों, प्रोफेशनल्स और आयोजकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विवेक अग्रवाल को उनकी सेवाओं और इवेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनकी पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। गौरतलब है कि इवेंट मैनेजर वे लोग होते हैं जो किसी भी शादी, सामाजिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कॉर्पोरेट इवेंट को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर अथक मेहनत करते हैं। मंच पर भले ही उनका चेहरा दिखाई न दे, लेकिन हर सफल आयोजन के पीछे उनकी योजना, प्रबंधन और टीमवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्ञात हो कि युवा इवेंट मैनेजर विवेक अग्रवाल रजवाड़ा लॉन के संचालक मंटू अग्रवाल के पुत्र तथा मनीष अग्रवाल के भतीजे है ।

चीचबंद में निर्माणाधीन सीसी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, मानकों की अनदेखी के आरोप

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जनपद पंचायत सिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत चीचबंद में निर्माणाधीन सीसी सडक़ के कार्य में गुणवत्ता संबंधी गंभीर लापरवाही सामने आने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि सडक़ निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार सडक़ निर्माण से पहले डाली गई मुरूम पर न तो पर्याप्त पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है और न ही उसे रोलर से दबाकर आवश्यक कम्पेक्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद सीधे कंक्रीट मटेरियल डालकर सडक़ का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में कंक्रीट को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक बाइब्रेटर का उपयोग भी नहीं किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर किसी भी विभागीय इंजीनियर की नियमित मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही है। तकनीकी पर्यवेक्षण के अभाव में निर्माण एजेंसी एवं संबंधित जिम्मेदारों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब मुरूम का उचित कम्पेक्शन नहीं किया जाएगा, पानी का छिडक़ाव नहीं होगा और बाइब्रेटर का उपयोग भी नहीं किया जाएगा, तो सडक़ की मजबूती एवं टिकाऊपन प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकारी धन से निर्मित होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगना लाजिमी है।

निर्माण स्थल की तस्वीरें भी कार्य में बरती जा रही कथित लापरवाही की ओर संकेत कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सीसी सडक़ निर्माण में आधार परत की उचित तैयारी, कम्पेक्शन, पानी का छिडक़ाव तथा कंक्रीट में बाइब्रेटर का उपयोग गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। इनकी अनदेखी से सडक़ की आयु कम हो सकती है तथा भविष्य में दरारें एवं अन्य तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराकर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं संबंधित विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

बरघाट के पीएम श्री कन्या विद्यालय में समर कैंप का भव्य समापन जनप्रतिनिधि भी हुए सम्मलित

बच्चो में रचनात्मक गतिविधियों के साथ मनाया गया समर कैंप समारोह छात्र छात्राओं में जागा उत्साह

राकेश अगरवार। हरीभूमि बरघाट। बरघाट नगर के पीएम श्री शासकीय कन्या विद्यालय बरघाट में 1 मई से 1 जून 2026 तक आयोजित समर कैंप के समापन समारोह का आयोजन किया गया।

संस्था के क्रीड़ा प्रभारी आशीष दीक्षित ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार, एवम जिला शिक्षा अधिकारी एस एस कुमरे के मार्गदर्शन तथा खेल एवम युवा कल्याण विभाग के सहयोग से पी एम श्री विद्यालय कैम्पस में आयोजित समर कैंप में खेल क्रिकेट, कबड्डी, पिट्टू,बेडमिंटन, टेबल टेनिस योगा के अलावा विभिन्न गतिविधियों में विशेषज्ञों द्वारा रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया गया जिसमे पेंटिंग में श्रीमती प्रीति राहंगडाले, आर्ट एंड क्राफ्ट में श्रीमती वीना मेश्राम,मेहंदी में श्रीमती ऋतु उईके, संगीत में अंकित गौतम, और योग में विलास चकोले,परसराम देशमुख,नम्रता मेश्राम,श्रीमती खिलेश्वरी पटले, कु सीता मसराम द्वारा प्रतिभागियों को निखारने में अपनी भूमिका निभाई।संस्था के पी एम श्री प्रभारी श्री अनिल अवधवाल द्वारा बच्चो को प्रोत्साहित किया गया। समर कैंप में निरंतर बदली छात्र छात्राओं में बदली दशो दिशाएं उत्कृष्टता रही अव्वल समर कैंप में बच्चों ने खूब सारे रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया समापन अवसर पर बच्चों को बिस्किट एवं फल वितरित किए गए तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही टेबल टेनिस में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बरघाट नगर का नाम गौरवान्वित करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष आदरणीया श्रीमती इमरता साहू , पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं एल्डरमैन श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर ,नगर परिषद उपाध्यक्ष , विकास जैन सांसद प्रतिनिधि,शिक्षक प्रकोष्ठ जिला संयोजक श्र नरेश राजपूत , नगर परिषद विधायक प्रतिनिधि सुजीत सूर्यवंशी,धारना भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तजेंद्र कटरे, एवं स्वयंसेवक आदरणीय श्री चुन्नीलाल जी,क्रीड़ा शिक्षक संदीप मिश्रा की विशेष उपस्थिति रही।

हरिभूमि
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
एजेंसी देना है
सिवनी जिले के अंतर्गत लखनादौन, बरघाट, कहानी में हरिभूमि अखबार की एजेंसी देना है इच्छुक व्यक्ति सुरक्षा निधि के साथ संपर्क करें।
हरिभूमि कार्यालय: प्लाट नं. 66/1 इंडस्ट्रियल एरिया,रिछाई जबलपुर (म.प्र)
मोबाइल नंबर: 9340637789, 9479623424

खबर संक्षेप

द्वारकाधीश राधाकृष्ण मंदिर में 108 सपत्नीक जोड़ों ने सुनी श्री सत्यनारायण कथा

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर शीलादेही स्थित श्री द्वारकाधीश राधाकृष्ण मंदिर एवं सहज संतोष आश्रम में भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर 108 सपत्नीक जोड़ों ने एक साथ बनारस एवं परमहंसी गंगा आश्रम से पधारे विद्वान शास्त्रीजी के श्रीमुख से भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा एवं वैदिक मंत्रोच्चार का श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया।

डॉ. आर. के. ठाकुर ने संभाला शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी के प्राचार्य का पदभार

हरिभूमि न्यूज सिवनी। केवलारी। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी में पदस्थ किरार समाज जिला मंडला ही नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र के गौरव राष्ट्रीय कवि डॉ. आर. के. ठाकुर ने प्राचार्य पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा नवयुवक मंडल राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रेरक वक्ता मनोज ठाकुर, एस बी आई बिजनिश मैनेजर ओमप्रकाश डहेरिया आदि ने उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

सतपुड़ा आईटीआई मे कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 5 जून को

हरिभूमि न्यूज सिवनी। सतपुड़ा प्रा. आईटीआई नागपुर रोड़ सिवनी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन 5 जून को सुबह 10 बजे से संस्थान परिसर सतपुड़ा आईटीआई मे किया जायेगा!प्राचार्य प्रदीप पंचबुद्धे जी ने बताया की देश की जानी मानी कंपनी अडानी मुंद्रा सोलर गुजरात द्वारा 10,12वी, बीएससी,बीए,आईटीआई, पोलिटेक्निक उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यार्थी भाग ले सकते है!

30 जिलों की महिलाएं जुटीं पतंजलि योग सम्मेलन में, सिवनी की महिला योग समिति सम्मानित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। महिला पतंजलि योग समिति का भव्य सम्मेलन एवं योग सेमिनार सिवनी में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 30 जिलों से आई महिला प्रतिभागियों ने सहभागिता कर योग, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला पतंजलि योग समिति की केंद्रीय प्रभारी डॉ. साध्वी देवप्रिया रहीं। दोनों अतिथियों ने सिवनी की महिला पतंजलि योग समिति की टीम को उनके उत्कृष्ट योगदान, सक्रिय सहभागिता और योग प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील

अब बिजली बिल की चिंता छोड़िए। भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2027 से पूर्व रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कराकर उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना में नामांकित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना के संबंध में हितग्राहियों को प्रमाणित एवं त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्हाट्सएप चैटबॉट "सोलर चाचा" का शुभारंभ किया गया है।

अवैध शराब बिक्री जोरों पर, परेशान महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

कहा- शराब माफियाओं का रक्षण कर रही है पुलिस

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

बालाघाट में बगदर्रा पंचायत के सरपंच, महिलाएं और पंचायत प्रतिनिधि बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार से गांव का माहौल प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं ने शिकायत की कि गांव के चौराहों पर अवैध शराब बेची जा रही है। इसके कारण शराब पीने वाले लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं और नशे की हालत में गाली-गलौज करते हैं। उनका कहना है कि इससे खुटिया, कटंगी, लिंगा, अमेड़ा, रट्टा और परसवाड़ा सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है।

सरपंच येशुला गुड्डु नगपुरे ने बताया कि अवैध शराब बिक्री का असर बच्चों और युवाओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली अभद्रता के कारण महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। पंचायत पंच चंद्रशेखर नगपुरे ने कहा कि शराब के कारण कई परिवारों में विवाद बढ़ रहे हैं और महिलाओं के साथ प्रताड़ना की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण थाना पुलिस को अवैध शराब बिक्री की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब बेचने वालों के नाम सौंपते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब के कारण क्षेत्र में मारपीट और अन्य विवादों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए, ताकि गांवों में कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल बेहतर बना रहे।

समिति नवेगांव, आरंभा, भेण्डारा, दीनी, बेनी, लड़सड़ा, मेण्डकी को स्पष्टीकरण जारी करने निर्देश

कम वसूली पर सीईओ ने लगाई फटकार!

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

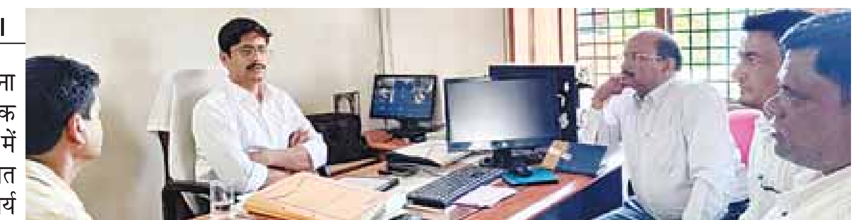

श्री मृणाल मीना कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में जिले में कालातीत एवं अकालातीत ऋणो की वसूली का कार्य प्रारंभ है। जिसको लेकर 03 जून को अभिनव सिंह बघेल ने डोंगरमाली शाखा अंतर्गत समिति लड़सड़ा का औचक निरीक्षण कर डिमांड के अनुरूप वसूली की समीक्षा किया गया। इस दौरान समिति में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नही पाये जाने पर समिति के दो कर्मचारियों को अवैतनिक किये जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पीओएस मशीन से खाद वितरण का मिलान किया गया तथा खाद स्टॉक को चैक किया गया। जहां खाद का स्टॉक सही पाया गया। इसके अलावा श्री बघेल ने सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए नये सदस्यों को नियमानुसार लाभ प्रदाय किये जाने के निर्देश दिए गए तथा शाखा डोंगरमाली पहुंचकर उन्होने अन्य समितियों के वसूली की गहन समीक्षा में पाया गया कि पैक्स समिति नवेगांव, आरंभा, भेण्डारा, दीनी, बेनी, लड़सड़ा, मेण्डकी की वसूली गत वर्ष की अपेक्षा कम वसूली को लेकर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए तथा उपस्थित कर्मचारियों को कम वसूली को लेकर फटकार लगाई गई। जबकि श्री बघेल द्वारा निरीक्षण के दौरान समिति डोंगरमाली की वसूली लक्ष्य के अनुरूप किये जाने पर समिति कर्मचारियों के कार्यो की प्रशंसा की गई उन्हे निर्देश दिए गए कि वसूली कार्य में और गति लाये। इसी तारतम्य में श्री बघेल सीईओ ने शाखा खैरलांजी और रामपायली पहुंचकर सदस्यता अभियान, कालातीत और अकालातीत, पशुपालन केसीसी, मत्स्य पालन केसीसी और मध्यमकालीन ऋण, ईआरपी, सीबीएस आदि बैंकिंग कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वर्तमान में वसूली का सीजन प्रारंभ है ऐसे में तय समय सीमा में समिति के कर्मचारी प्रतिदिन वसूली कार्य में तत्परता लाये ताकि प्रदाय लक्ष्य अनुसार वसूली की जा सके। श्री बघेल ने समितियों के साफ-सफाई को लेकर निर्देश दिए और उपस्थित किसानों से भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान शाखा प्रबंधक आई.आर. भगत रामपायली, मुकेश ठाकरे खैरलांजी, जयकुमार नंदनवार डोंगरमाली, एस.डी. अंकर, विनोद बिसेन सहित समिति के कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवैध रूप से धान बीज विक्रय करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

बिना लायसेंस के सानू पटले और पलक बिसेन द्वारा गांव में घूम-घूम कर बेचा जा रहा था धान बीज

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। विकासखंड बैहर के विभिन्न ग्रामों में बिना वैध अनुज्ञप्ति के धान बीजों का अवैध विक्रय किए जाने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना बैहर को पत्र प्रेषित किया है।

कृषि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनांक 31 मई 2026 को ग्राम गोहारा तथा 01 जून 2026 को ग्राम भंडेरी के काशीटोला एवं ग्राम पोला-पटपरी में श्री कृषक साथी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, बैहर के प्रोपराइटर श्री सानू पटले एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न कंपनियों के धान बीज वाहन क्रमांक MP50ZG6496 के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को बेचे जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर कृषि विभाग बैहर के अनुविभागीय कृषि अधिकारी (एसडीओ) श्री एस.आर. धुर्वे द्वारा 02 जून को ग्राम काशीटोला एवं पोला-पटपरी तथा 03 जून को ग्राम गोहारा पहुंचकर किसानों के घरों में वितरित बीजों का सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान पंचनामा तैयार कर तथ्यों का संकलन किया गया।

प्राथमिक जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कंपनियों के धान बीज, जिनमें केशव खनक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (गोंदिया, महाराष्ट्र), जयकुंड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (वडोदरा, गुजरात), जीनोमिक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (सिकंदराबाद, तेलंगाना) तथा सुमनजली सीड्स एंड फार्मर्स (हनमकोंडा, तेलंगाना) के बीज शामिल हैं, बिना वैध बीज अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में विक्रय किए जा रहे थे।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार वाहन क्रमांक MP50ZG6496 के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के किसानों को अवैधानिक रूप से बीज बेचे जाने की पुष्टि हुई है। कृषि विभाग का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां किसानों के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आती हैं तथा इससे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, बीज अधिनियम 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 3 का उल्लंघन होता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ कृषि श्री एस.आर. धुर्वे ने श्री सानू पटले निवासी भीकेवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, श्री पलक बिसेन निवासी भंडेरी, तहसील बैहर तथा वाहन मालिक श्री कुंजेलाल/नुरेलाल हिरवाने निवासी भोरवाही लिंगा, विकासखंड परसवाड़ा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी बैहर को पत्र भेजा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध विक्रय गतिविधि की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।

मॉयल में अनुकम्पा नियुक्ति आवेदकों से प्रबंधन का संवाद, नई नीतियों और लंबित प्रकरणों पर दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत MOIL Limited द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पात्र आवेदकों एवं उनके परिवारजनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मॉयल मुख्यालय नागपुर से आए अधिकारियों ने अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित केंद्र सरकार की नवीन नीतियों, नियमों तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

जानकारी के अनुसार मॉयल लिमिटेड की भरवेली एवं उकवा खदानों में विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए कर्मचारियों और कामगारों के परिवारों के उन सदस्यों को इस संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जो अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र हैं अथवा जिन्होंने इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम में मॉयल मुख्यालय नागपुर से प्रमुख प्रबंधक (कार्मिक) आशीष सूर्यवंशी एवं श्रीमती पूजा वर्मा ने उपस्थित आवेदकों के साथ वन-टू-वन चर्चा की।

अधिकारियों ने आवेदकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुकम्पा नियुक्ति के वर्तमान मापदंडों से अवगत कराया तथा यह भी बताया कि अनेक प्रकरण अब तक लंबित क्यों हैं और उन्हें स्वीकृति मिलने में किन प्रशासनिक एवं नीतिगत कारणों से विलंब हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 के बाद केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसके कारण प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक जटिल और नियमबद्ध हो गई है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से मॉयल लिमिटेड में सामान्य परिस्थितियों में अनुकम्पा नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब केवल कार्यस्थल पर हुई घातक दुर्घटना (फेटल एक्सीडेंट) में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। वहीं बीमारी, प्राकृतिक मृत्यु अथवा अन्य कारणों से दिवंगत होने वाले कर्मचारियों और कामगारों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर 30 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है।

आदिवासी समाज की आवाज़ बुलंद करना हमारी प्राथमिकता : विधायक मधु भगत

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने कहा है कि देश का आदिवासी समाज आज अपने अधिकारों, अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्षों से आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और सामाजिक सम्मान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार केवल बड़े-बड़े वादे करने तक सीमित दिखाई देती है। वास्तविकता यह है कि जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और उनकी आवाज़ को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

विधायक मधु भगत ने कहा कि आदिवासी समाज देश की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों का वास्तविक संरक्षक रहा है। इसके बावजूद आज भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। सरकारें विकास के दावे तो करती हैं, लेकिन आदिवासी अंचलों की वास्तविक स्थिति इन दावों की पोल खोल देती है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को केवल चुनावी समय पर याद किया जाता है, जबकि उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते। वनाधिकार कानून, पेसा एक्ट और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन आज भी चुनौती बना हुआ है। यदि सरकार वास्तव में आदिवासियों के हित में काम करना चाहती है, तो उसे इन कानूनों को पूरी मजबूती के साथ लागू करना होगा।

मधु भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है। पार्टी ने समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनसे आदिवासी वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को मजबूत करे।

उन्होंने कहा कि आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि युवा सशक्त होंगे तो समाज भी मजबूत होगा। सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया जल गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण

पीएचई विभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा ग्राम स्तर पर पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसी क्रम में 3 जून 2026 को जनपद पंचायत खैरलांजी में महिला एवं बाल विकास विभाग के खरखड़ी, भौरगढ़ एवं खैरलांजी सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम का आयोजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के कार्यपालन यंत्री बी.एल. उइके के मार्गदर्शन में पीएचई उपखंड खैरलांजी द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में ब्लॉक समन्वयक मोहिनी पटले एवं केमिस्ट नेमसिंह मर्सकोले ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल गुणवत्ता परीक्षण की तकनीकी जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान खरखड़ी, भौरगढ़ और खैरलांजी सेक्टर की 77 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फील्ड टेस्टिंग किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उनकी एफटीके यूजर आईडी भी तैयार की गई। यह कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हरीश झा, शीतल मिश्रा, रानी सिंह राजपूत, परमानंद ठाकरे, मोहिनी पटले एवं श्रुति डहाटे के सहयोग से संपन्न हुआ।प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फील्ड डेमो रहा, जिसमें आंगनवाड़ी एवं स्कूलों से लाए गए पेयजल नमूनों की एफटीके किट के माध्यम से मौके पर ही जांच कराई गई। कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बताया गया कि पानी में मौजूद विभिन्न तत्वों की पहचान कैसे की जाती है तथा उसकी गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार किया जाता है। प्रशिक्षण में पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रमुख मानकों की जानकारी दी गई, जिनमें पीएच मान (अम्लीयता एवं क्षारीयता), फ्लोराइड की मात्रा, आयरन (लौह तत्व) की मात्रा तथा पानी की कठोरता (हार्डनेस) शामिल रही। कार्यकर्ताओं ने स्वयं परीक्षण कर इन मानकों की जांच की प्रक्रिया को समझा।प्रशिक्षण के दौरान पीएचई उपखंड कटंगी के सहायक यंत्री जितेंद्र कारमेघे ने बताया कि कटंगी और खैरलांजी उपखंडों के बीच केवल एक प्रयोगशाला होने के कारण सभी गांवों के जल नमूनों की नियमित जांच प्रयोगशाला में कर पाना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से ग्राम स्तर पर एफटीके किट उपलब्ध कराई गई है ताकि स्थानीय स्तर पर ही जल गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के कुओं, हैंडपंपों तथा नल-जल योजनाओं के जल स्त्रोतों की मानसून पूर्व अनिवार्य रूप से जांच करें, जिससे जलजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। उपयंत्री विनोद कुमरे ने भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के सभी पेयजल स्त्रोतों का वर्ष में कम से कम दो बार मानसून से पहले और मानसून के बाद जल परीक्षण अवश्य करें।प्रशिक्षण के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपनी-अपनी आंगनवाड़ियों से लाए गए पेयजल नमूनों की जांच कर सीखी गई तकनीकों का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों एवं नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सहायक यंत्री जितेंद्र कारमेघे, उपयंत्री विनोद कुमरे, अजय भरतकर, जिला समन्वयक शीतल मिश्रा, हरीश झा, ब्लॉक समन्वयक रानी सिंह राजपूत, मोहिनी पटले, परमानंद ठाकरे, श्रुति डहाटे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी लकेश ऊके सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

जंगल के कानून को चुनौती! सुकर के मांस के साथ तीन दबोचे, चौथा आरोपी वन अमले को चकमा देकर फरार

टेमनी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, जर्मन के डिब्बे में छिपाकर रखा गया था मांस, वन्यजीव शिकार के संगठित नेटवर्क की आशंका

हरिभूमि न्यूज लांजी।

पश्चिम वन परिक्षेत्र लांजी के कोचेवाही बीट अंतर्गत ग्राम टेमनी में बुधवार को वन विभाग ने ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार और मांस तस्करी की आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है। वन अमले ने लगभग तीन किलो सुकर के मांस के साथ तीन आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी कार्रवाई के दौरान मौके से फरार होने में सफल रहा।जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने दोपहर करीब 2 बजे ग्राम टेमनी में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान जितेंद्र पिता दशरथ के घर से लगभग तीन किलो सुकर का मांस बरामद किया गया। मौके पर मौजूद महेश पिता भालचंद (58 वर्ष) एवं शंकर पिता रूपचंद (50 वर्ष), निवासी चौंदाटोला, को भी हिरासत में लिया गया।बरामद मांस को जर्मन के डिब्बे में छिपाकर रखा गया था, जिससे स्पष्ट है कि पूरे मामले को गुप्त रखने का प्रयास किया जा रहा था।

वन विभाग की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद मांस को सबसे पहले हरिचंद धोबी के घर लाया गया था। लेकिन जैसे ही वन अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा, हरिचंद धोबी मौके से फरार हो गया। इससे संदेह और गहरा गया है कि मामले में केवल कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक बड़े अवैध शिकार तंत्र की भूमिका हो सकती है। वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि सुकर का शिकार कब, कहां और किन परिस्थितियों में किया गया। साथ ही फरार आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।इस पूरी कार्रवाई में रेंजर सपन ताम्रकार, डिप्टी रेंजर दिलीप ऊके, रविंद्र सोनवाने, पवन पटले सहित वनरक्षक रत्नकला भलावी, सीमा घोरमारे, विशाल आसटकर, भारतलाल नेवारे, यशवंत बिसेन और मुकेंद्र तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इनका कहना है

इस मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है। वन विभाग उसकी तलाश कर रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

राकेश कुमार अड़कने, उपवनमंडल अधिकारी वन विभाग लांजी

जिला स्तरीय बैंकर्स एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न

बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित ऋण प्रकरणों, उनकी स्वीकृति एवं ऋण वितरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वय अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने कहा कि शासन की स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सभी विभागों एवं बैंकों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

ओरिएण्टल इंजीनियरिंग कॉलेज लालबर्रा (बालाघाट)
B.Tech
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
Polytechnic
माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
प्रवेश प्रारंभ 2026-27
Balaghat Road Lalburra,Teh, Lalburra, Dist. Balaghat M.P. 9202131331, 9202121331

DGET/NCVT/ से मान्यता प्राप्त
प्रवेश प्रारंभ
जिले की एक मात्र ISO-9001-2008 प्रमाणित संस्था
अरिहंत प्रा.आई.टी.आई.
लालबर्रा रोड गर्रा बालाघाट फोन - 6263882617, 9425875737
- ट्रेड -
इलेक्ट्रीशियन
फिटर
अरिहंत इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर्स &आई.
फोन - 7999525911, 9425892823
BCA
M.Sc.(CS)
DCA
PGDCA
विशेषताएं:-

सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट
ENGINEERING | PHARMACY | AGRICULTURE
ADMISSION OPEN 2026-27
POLYTECHNIC
B.TECH | M.TECH
Part Time/Full Time
• D. PHARMACY
• B. PHARMACY
• M. PHARMACY
• B.Sc. (Hons.)Ag.
• B.Tech (Agri) Engg.
• M.Sc. (Ag.)
ABM
LAW • B.A. LL.B. • LL.B. • LL.M.
छात्रवृत्ति SC/ST/OBC
कैम्पस : वारासिवनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट (म.प्र.) | 9174192111, 9174202111